क्या भारत को अपनी 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए?

लेखक - दिनकर पेरी (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

23 अगस्त, 2019

"भारत के पास अपनी नीति बदलने का कोई कारण नहीं है, जो प्रतिक्रियात्मक है लेकिन पहले पहल नहीं की जाएगी।"

पिछले हफ्ते, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि परमाणु हथियारों पर भारत की 'नो फर्स्ट यूज' (NFU) नीति का भविष्य "परिस्थितियों" पर निर्भर करेगा। श्री सिंह के बयान से भारत की इस नीति और परमाणु सिद्धांत के संभावित संशोधन पर आशंका बढ़ गई है। दिनकर पेरी ने राजेश राजगोपालन (प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) और मनप्रीत सेठी (प्रतिष्ठित फेलो, सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज) से हुई एक बातचीत में इन चिंताओं को संबोधित किया है। इस आलेख में हम नो फर्स्ट यूज नीति पर उठ रहे सवालों पर चर्चा करेंगे।

प्रश्नः- रक्षा मंत्री के बयान का क्या मतलब है और क्या यह भारत की नो फर्स्ट यूज नीति और परमाणु सिद्धांत में एक संभावित बदलाव का संकेत देता है?

राजेश राजगोपालनः मुझे यकीन नहीं है कि यह वास्तव में भारत की एनएफयू (NFU) नीति यानि नो फर्स्ट यूज नीति का संशोधन है क्योंकि रक्षा मंत्री ने कहा है कि भविष्य में परिस्थितियों के आधार पर नीति में बदलाव किये जा सकते हैं और हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। सिद्धांत केवल तब तक के लिए मान्य है जब तक सरकार कहती है कि यह मान्य है। यह सुझाव देना मूर्खता होगी कि सिद्धांत बदल नहीं सकते हैं या वे हर समय और सभी परिस्थितियों में एक ही समान रहेंगे।

यह संभवतः पाकिस्तान के लिए एक संकेत हो सकता है कि उसे आने वाले समय में भारत के संयम की और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि संभवतः बयान का अतिरंजित पठन भी होगा। मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह का बयान पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान से कुछ अलग है। उन्होंने एक पुस्तक लॉन्च में कहा था कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें तब तक का इंतजार क्यों करना पड़ता है जब तक कि हमारे ऊपर हमला हो नहीं जाता है। हालांकि, बाद में यह स्पष्ट किया गया था कि उनका बयान सरकार की नीति के बजाय उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण था। मैं सिद्धांत में बदलाव के संकेत के रूप में श्री सिंह के बयान को नहीं देखता और जाहिर है कि अगर हमने नो फर्स्ट यूज नीति को बदल दिया, तो यह विशेष रूप से उपयोगी नहीं होगा।

प्रश्नः- यह पहली बार नहीं है जब किसी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी ने इस तरह का बयान दिया हो। भारत के रुख में संशोधन को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है, खासकर नो फर्स्ट यूज नीति पर। नो फर्स्ट यूज नीति में संशोधन 2014 में भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल था। हालांकि, यह 2019 के घोषणा पत्र में शामिल नहीं था। क्या यह सब बिंदु परिवर्तन का संकेत है?

मनप्रीत सेठीः मैं प्रोफेसर राजगोपालन द्वारा श्री सिंह के बयान की व्याख्या पर काफी हद तक सहमत हूँ। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही सामान्य कथन है। जैसे-जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं, नीतिगत समायोजन होते रहते हैं। मुझे रक्षा मंत्री के कथन में कुछ भी गलत नहीं प्रतीत होता। जैसा कि आपने भाजपा के घोषणा पत्र का उल्लेख किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। व्यक्तिगत राय, जिनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और बड़े-बड़े पदों पर मौजूद हैं, ने

नो फर्स्ट यूज नीति के संशोधन के इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन उन्होंने नो फर्स्ट यूज नीति के किसी भी संशोधन का उल्लेख नहीं किया, जब वे उन पदों पर थे। पिछले साल के अंत में, भारत की बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत के पहले गश्त की घोषणा के अवसर पर, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया था कि भारत के परमाणु सिद्धांत का मूल सिद्धांत 'नो फर्स्ट यूज' नीति होगा। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी नीति है और देश के पास इसे बदलने का कोई कारण नहीं है।

प्रश्नः- पिछले कुछ वर्षों में, भारत की पारंपरिक मनोदशा में एक बड़ा बदलाव आया है। जिसे 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल के बालाकोट एयरस्ट्राइक में देखा जा सकता है। इस घटना ने इस पुरानी धारणा को भी बदल दिया है कि दोनों देश परमाणु शक्ति से संपन्न होने के कारण आपस में पारंपरिक युद्ध नहीं कर सकते। इस संदर्भ में, क्या भारत के लिए परमाणु संबंधित नीति पर स्थिरता बेहतर नहीं होगी, ताकि पारंपरिक युद्ध के लिए अवसर बचा रहे?

राजेश राजगोपालनः बिल्कुल। मेरा मतलब है कि हम परमाणु मोर्चे पर स्थिरता चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्थिरता खतरे में थी। आतंकवादियों को भेजने के संदर्भ में पाकिस्तान हर बार परमाणु कार्रवाई के इस दलदल को बार-बार उठाता रहता है। लेकिन यह भारत की प्रतिक्रिया को बाधित करने का एक तरीका है, भारत को उन प्रकार के हमलों के लिए सैन्य रूप से प्रतिक्रिया देने से रोकने का यह एक तरीका है। इसके पीछे का कारण यह है कि यदि पाकिस्तान परमाणु के मुद्दे को उठाता है, तो वैश्विक स्तर पर इसे परमाणु खतरे के रूप में देखा जाएगा, जिससे भारत को प्रतिक्रिया करने में बाधा होगी।

उदाहरण के लिए, कारगिल में, जब हमने पाकिस्तान की वायु सेना को पहाड़ की ऊँचाइयों से विस्थापित करने के लिए वायु शक्ति का उपयोग शुरू किया, तो शुरू में पाकिस्तान ने इसकी शिकायत की। इसने कहा कि इससे परमाणु युद्ध हो सकता है। लेकिन बहुत जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह, 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान, पाकिस्तान ने फिर से परमाणु यद्ध की संभावना को व्यक्त किया। लेकिन इनमें से प्रत्येक मामले में हमने कोई वृद्धि नहीं देखी। इन मुद्दों के बीच में कई परतें हैं और वे ऐसी परतें हैं जिनसे पाकिस्तान को फायदा होता है क्योंकि यह वास्तव में बालाकोट जैसी किसी भी चीज या सर्जिकल स्ट्राइक के लिए परमाणु युद्ध नहीं हो सकता है।

इसलिए, हाँ, हम परमाणु स्थिरता चाहते हैं और परमाणु स्थिरता मौजूद भी है। पाकिस्तान द्वारा यह सिर्फ एक अतिशयोक्ति है कि परमाणु स्थिरता हमेशा खतरे में है और हम जो कुछ भी करते हैं उससे परमाणु खतरे की संभावना बढ़ जाती है।
हमने बार-बार दिखाया है कि हम परमाणु स्तर के करीब जाने के बिना भी कार्रवाई कर सकते हैं।

प्रश्नः- पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को समुद्र में डालने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से बाहर हो गया है। क्या इन घटनाओं का परमाणु क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ेगा?

मनप्रीत सेठीः सबसे पहले, मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी भी अस्पष्टता को भारत के सिद्धांत में लाया गया है। मुझे लगता है कि भारत अपनी नो फर्स्ट यूज नीति पर बहुत स्पष्ट है।

नो फर्स्ट यूज नीति को हटाने से भारत एक समस्याग्रस्त स्थिति में आ जाएगा क्योंकि एक विश्वसनीय 'प्रथम उपयोग' के लिए आपको विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का निर्माण करना होगा, जिसका अर्थ होगा एक अलग प्रक्षेपवक्र। अगर भारत को नो फर्स्ट यूज नीति को हटाना ही था, तो वह अब तक हथियारों की दौड़ में शामिल हो गया होता।

चीन की प्रतिक्रिया के संदर्भ में, मैं भारत की क्षमता निर्माण के जवाब में कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं देख रहा हूँ। किसी भी मामले में, इसके पास परमाणु और वितरण प्रणाली है। यह निश्चित रूप से एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को बदनाम करने के अवसर का उपयोग करेगा। इसलिए, परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह का सदस्य या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सीट के लिए भारत का दावा इसके परिणामस्वरूप तनाव में आ जाएगा।

सच कहूँ तो, जहाँ तक बाकी दुनिया की प्रतिक्रिया का सवाल है, हम पहले से ही ऐसी स्थिति में हैं जहाँ हथियारों का नियंत्रण चरमरा रहा है: यू.एस. की परमाणु मनोदशा की समीक्षा एक बार फिर सीमित परमाणु युद्ध की बात कर रही है। बाकी दुनिया

इस बदलाव के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करेगी, सिवाय बयानबाजी के स्तर पर जहां सिर्फ आलोचना की जा सकती है। इसलिए, मेरी चिंता नो फर्स्ट यूज नीति में परिवर्तन पर दुनिया की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं है, बल्कि पहली बार उपयोग करने योग्य बनने के लिए वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं में निवेश की दृष्टि से भारत द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के संदर्भ में है।

प्रश्नः- पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से अपने परमाणु शस्त्रागार में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है और पारंपरिक एवं परमाणु के बीच की खाई को पाटने की कोशिश कर रहा है। मैं भारत के न्यूक्लियर ट्राइऐड पूरा होने के बाद पाकिस्तान द्वारा पारंपरिक पनडुब्बियों पर परमाणु हथियार लगाने के प्रयासों का उल्लेख कर रहा हूँ। क्या यह पारंपरिक और परमाणु के बीच की रेखा को धुंधला करता है और नए जोखिम पैदा करता है?

राजेश राजगोपालनः हाँ, जब आप दोहरे उपयोग वाले वितरण वाहनों और हथियार प्रणालियों का उपयोग करते हैं तो एक समस्या है। यह वह समस्या है जिसका हमने अतीत में सामना किया है। विदित हो कि पाकिस्तान कुछ एयरबेस में अपने परमाणु हथियार को रखे हुए है। हम उस एयरबेस पर हमला करने से खुद को रोकेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान अपने इस पारंपरिक हमले को परमाणु हथियारों पर हमला समझने की गलती करे। इसलिए, जब भी आपके पास दोहरे उपयोग वाले हथियार होते हैं, तो समस्या होती है। एक समस्या यह भी है जब दोनों एक बेस या पनडुब्बी को परमाणु हथियारों से युक्त समझने की गलती करें। दोनों एक-दूसरे के उस बेस पर हमला करने से अपने आप को रोकेंगे, क्योंकि हम यह संदेश नहीं देना चाहेंगे कि हम उनके परमाणु हथियारों पर हमला कर रहे हैं। दूसरी ओर, यह और भी बड़ी समस्या होगी जब पाकिस्तान इन दोहरे उपयोग की प्रणालियों का प्रयोग करेगा। अगर कोई पारंपरिक मिसाइल या कम दूरी की मिसाइल हम पर लॉन्च की जाती है, तो हमें नहीं पता होगा कि यह पारंपरिक मिसाइल है या परमाणु मिसाइल है और इसलिए यह संभव है कि कोई इसे एक आने वाले परमाणु हमले के रूप में समझने में भूल कर दे। यहाँ तक कि हमारे स्वयं के शस्त्रागार में परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के वॉरहेड हैं।

प्रश्नः- 2013 में, पाकिस्तान के टैक्टिकल परमाणु हथियार या युद्धक्षेत्र परमाणु हथियार पेश करने के बाद, भारत ने स्पष्ट किया कि वह स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल परमाणु युद्ध के बीच अंतर नहीं करेगा और बड़े पैमाने पर प्रतिक्रियात्मकता का सिद्धांत लागू करेगा। दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के साथ हाल ही में रेखाओं के बीच की दूरी धुंधली हो जाने के बाद, क्या वर्तमान परमाणु सिद्धांत आगे भी लागू होगा?

राजेश राजगोपालनः मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि जो भी भारतीय स्थिति है, किसी भी हमले को एक परमाणु हमला माना जाएगा, भले ही वह एक स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार हो या टैक्टिकल परमाणु युद्ध हो क्योंकि किसी भी हमले को पूर्ण पैमाने पर परमाणु हमला ही माना जाएगा। भारतीय सिद्धांत भी पर्याप्त रूप से लचीला है। परमाणु हमले के मामले में बड़े पैमाने पर प्रतिक्रियातामकता का एक विकल्प है। उदाहरण के लिए, भारत प्रक्रियात्मक या एक सीमित परमाणु हमले में एक और छोटे परमाणु बम का उपयोग करने का निर्णय ले सकता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सिद्धांत को उसी के जवाब में बदलना होगा। सभी सिद्धांत कहते हैं कि हम पहले हमला करने की पहल नही करेंगे और हम केवल जवाबी कार्रवाई करेंगे। हमारी मनोदशा और सिद्धांत अनिवार्य रूप से केवल प्रतिक्रियात्मक है। हम पहले पहल कभी नहीं करेंगे।

GS World
Committed to Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

   1. 1957 में भारत ने अपना पहला परमाणु अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया।
   2. भारत ने अपना आण्विक सिद्धांत (Nuclear Doctrine) 2003 में घोषित किया था।
   3. आण्विक सिद्धांत के अनुसार आण्विक अस्त्र के प्रयोग का निर्णय प्रधानमंत्री अथवा उसके द्वारा नामित उत्तराधिकारी ही करेगा।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) 2 और 3

   (c) उपर्युक्त सभी (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements -**

   1. In 1957, India established its first Atomic Research Center.
   2. India declared its Nuclear Doctrine in 2003.
   3. According to the Nuclear Doctrine the decision of the use of Nuclear weapon could only be taken by the Prime Minister or a person nominated by him.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1 (b) 2 and 3

   (c) All of the above (d) None of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए भारत द्वारा नाभिकीय हथियारों के प्रयोग के संबंध में अपनायी गई 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' वर्तमान में कितनी प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. Observing the global scenario, "No First Use Policy" adopted by India regarding the use of Nuclear weapons is how much relevent at present? Discuss.

(250Words)

नोट : 22 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

Committed